प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
17.02.2026 / प्रादेशिक समाचार / 18:00बजे

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार गग्गल एयरपोर्ट और गगरेट में ज़मीन के बेनामी सौदों की जांच करवाएगी। उन्होंने इसके लिए पुलिस की एस.आई.टी के गठन की घोषणा की। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने गगरेट के विधायक राकेश कालिया द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों स्थानों पर हुई ज़मीन की बेनामी खरीद और उसमें कथित दलाली दिए जाने के मामले की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने पैसे का बेनामी लेन–देन किया है, तो उसकी ज़मीन ज़ब्त होगी और उसे मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि जांच में ऐसा कोइ मामला सामने आता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व मूल प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के तहत अभी तक 4 हज़ार 6 सौ 49 लोगों को एक हज़ार 4 सौ 60 करोड़ रूपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ये राशि भू–अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभावितों के खाते में ट्रांसफर की गई है।

त्रत किया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को यह भी चेताया कि वह विधायक निधि के ज्यादा पत्र जारी न करें।

आरडीजी चर्चा

विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज भी राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी पर प्रस्तुत सरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रही। चर्चा में भाग लेते हुए उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष को इस मुद्दे पर घेरा और पूछा कि वे आरडीजी बंद होने के पक्ष में हैं या विरोध में। उन्होंने कहा कि प्रदेश को आरडीजी मिले, ये संविधान में अधिकार दिया गया है और आरडीजी मिलना हिमाचल का अधिकार है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उप–मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के निर्माण के समय ये स्पष्ट था कि इस पर्वतीय राज्य को केंद्र सहायता करेगा। उन्होंने कहा कि 17 मई से 12 राज्यों में आरडीजी पर निर्भरता केवल एक प्रतिशत के आसपास है। ऐसे राज्यों को इसकी विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन हिमाचल को इसकी ज़रूरत है।

आरडीजी चर्चा–2

दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आरडीजी के मुद्दे पर सरकार अपना पक्ष नहीं बता रही है, केवल राजनीतिक लाभ के लिए संकल्प लेकर आई है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार अगर आरडीजी को लेकर राजनीतिक लड़ाई ही लड़ना चाहती है तो विपक्ष भी इसके लिए तैयार है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आरडीजी के मुद्दे को लेकर भाजपा अपने स्तर पर केंद्र सरकार के समक्ष मुद्दा उठा रही है। उन्होंने कहा कि उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री अपनी भड़ास निकालने के लिए सदन में भाजपा को दोषी ठहरा रहे हैं।

नरेश बंसल

उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026–27 के केंद्रीय बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है। धर्मशाला में आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि बजट में रेलवे, विमानन और जल परिवहन में बड़े प्रावधान किए गए हैं ताकि कनेक्टिविटी बढ़े और आर्थिक विकास को गति मिले। नरेश बंसल ने बजट को "शानदार और आमजन हितैषी" बताया। उन्होंने कहा कि 53 लाख करोड़ रुपये से अधिक के इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आर्थिक विकास और नियंत्रित महंगाई को सुनिश्चित किया है।

नरेश बंसल ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। डॉ. बंसल ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट पर्यटन और पर्यावरण को बढ़ावा देने वाला है।

प्रदर्शन

प्रदेश पैंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आज शिमला के चौड़ा मैदान में धरना–प्रदर्शन किया। समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने बताया कि सरकार द्वारा पैंशनरों की मांगों को बार–बार अनेदखा किया जा रहा है।

———————————————————————————————————